अक्कयनाइकर

बनाम

ए.ए.ए. कोटचादैनैदु और अन्य

23 सितम्बर 2004

[अशोक भान और एस.एच. कपाड़िया, जे.जे.]

परिसीमा अधिनियम, 1963-अनुच्छेद 136-निष्पादन याचिका-सीमा संगणना-डिक्री के निष्पादन के लिए विधायी बाधा - डिक्री का संशोधन

विधायी हस्तक्षेप द्वारा प्रतिबंध हटाने और डिक्री में संशोधन के बाद, निधार्रित : सीमा अवधि की संगणना डिक्री में संशोधन की दिनांक से की जाएगी, न कि डिक्री की दिनांक से क्योंकि संशोधन के बाद ही डिक्री प्रवर्तनीय हो गयी थी, अनुच्छेद में प्रवर्तनीय को उस डिक्री के संदर्भ में समझा जाना चाहिए जिसे लागू करने की मांग की गई है - तमिलनाडु ऋणी कृषक (अस्थायी राहत) अधिनियम, 1975- धारा 3, 4 और 5 - तमिलनाडु ऋणी कृषक (अस्थायी राहत) अधिनियम, 1976 - तमिलनाडु ऋण राहत अधिनियम, 1978.

अपीलकर्ता-डिक्रीदार द्वारा प्रतिवादी निणीर्त ऋणी के वसूली वाद 2.5.1973 को डिक्री किया गया था। 1973 में प्रस्तुत निष्पादन याचिका को तमिलनाडु ऋणग्रस्त कृषक (अस्थायी राहत) अधिनियम, 1976 के अधिनियमन द्वारा विधायी हस्तक्षेप के कारण बंद कर दिया गया था। इसके बाद, तमिलनाडु ऋण राहत अधिनियम, 1978 के आधार पर, निणीर्त ऋणी के आवेदन पर, निष्पादन न्यायालय ने डिक्री को 1979 में न्यून कर दिया। इसके बाद डिक्री धारक ने 1989 में निष्पादन याचिका दायर की। निणीर्त ऋणी ने इसे परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 136 के तहत परिसीमा द्वारा

वर्जित मानते हुए आपत्ति की क्योंकि इसे 12 साल से अधिक समय पहले दायर किया गया था। निष्पादन न्यायालय ने यह कहते हुए याचिका स्वीकार कर ली कि सीमा उस दिन से शुरू होगी जिस दिन डिक्री में संशोधन किया गया था क्योंकि उसी दिन से डिक्री लागू करने योग्य थी। उच्च न्यायालय ने माना कि सीमा अवधि की गणना मूल डिक्री की तारीख से की जानी थी।

इस न्यायालय में अपील में अपीलकर्ता-डिक्री धारक ने तर्क दिया किसीमा बिंदु वह तारीख है जब डिक्री लागू करने योग्य हो जाती है और वर्तमान मामले में डिक्री तब लागू करने योग्य हो जाती है जब विधायी बाधा उठाई गई थी और विधायी हस्तक्षेप के कारण डिक्री में संशोधन किया गया था।

अपील की अनुमति देते हुए, न्यायालय ने कहा: लिमिटेशन एक्ट, 638 के अनुच्छेद 136 में "प्रवर्तनीय" शब्द 1963 को उस डिक्री के संदर्भ में समझा जाना चाहिए जिसे लागू करने की मांग की गई है। वर्तमान मामले में डिक्री-धारक ने वर्ष 1973 में ही निष्पादन के लिए एक आवेदन दायर किया था, लेकिन विधायी हस्तक्षेप के कारण इसकी कार्यवाही बंद कर दी गई और अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई, जो विधायिका द्वारा तमिलनाडु ऋण राहत अधिनियम, 1978 लागू करने और स्केलिंग प्रदान करने तक जारी रही। कृषकों द्वारा प्राप्त ऋणों को कम करना, जिसमें पहले से पारित डिक्री भी शामिल है। इस विधायी अधिनियम के अनुसरण में डिक्री-धारक के पक्ष में पारित डिक्री को काफी हद तक कम कर दिया गया और डिक्री को ऋण राहत अधिनियम के संदर्भ में 18.10.1979 को संशोधित किया गया। यह वह डिक्री है जो लागू करने योग्य बन गई। इस तिथि से पहले डिक्री-धारक विधायी हस्तक्षेप के कारण अपने डिक्री को लागू नहीं कर सका। मूल डिक्री लागू नहीं की जा सकी। यह केवल संशोधित डिक्री है जिसे लागू किया जा सकता है। जब किसी डिक्री के

निष्पादन के लिए विधायी रोक थी और बाद में विधायी हस्तक्षेप के कारण डिक्री को न्यून करना और संशोधित करना पड़ा, तो डिक्री की प्रवर्तनीयता रोक समाप्त होने पर या डिक्री में संशोधन और कमी होने की तारीख से शुरू होगी। यदि 12 वर्ष की अवधि को डिक्री के संशोधन की तिथि से गिना जाता है तो डिक्री धारक द्वारा 18.9.1989 को दायर निष्पादन याचिका परिसीमा की अवधि के भीतर है। (645-ई-एच; 646-ए)

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: 1999 की सिविल अपील संख्या 160.

सी.आर.पी. 1992 की संख्या 3540. में मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णय एवं आदेश दिनांक 29.1.98 से

अपीलकर्ता की ओर से आर. नेदुमारन और एम.ए. चिन्नासामी।

ऋषिराज बोरूआ और के.के. मणि उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय भान, जे. द्वारा पारित किया गया।

अपीलकर्ता/डिक्री धारक, 1992 के सीआरपी संख्या 3540 में मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले और आदेश के खिलाफ व्यथित है, जिसमें उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी द्वारा दायर नागरिक पुनरीक्षण याचिका की अनुमति देते हुए निष्पादन को खारिज कर दिया है। अपीलकर्ता द्वारा दायर याचिका, न्यायालय की अनुमति से वर्तमान अपील दायर की है।

अपीलकर्ता/डिक्री धारक (इसके बाद "डिक्री धारक"के रूप में प्रयुक्त होगा)

ओएस क्रमांक 322/1972, 18,219 रुपये की राशि में डिक्री की मांग के लिए दायर किया गया। सहमत दर के साथ 18,912 रु. 12% प्रति वर्ष की दर से ब्याज प्रतिवादी/निर्णय ऋणी (इसके बाद "निर्णय ऋणी"के रूप में संदर्भित) द्वारा निष्पादित

वचन पत्र दिनांक 3.6.1968 पर देय मूलधन और ब्याज पर होगा । मुकदमे का फैसला 2.5.1973 को हुआ। यह डिक्री पक्षकारों के बीच अंतिम हो गई।

डिक्री धारक ने 1973 की निष्पादन याचिका संख्या 226 दायर की लेकिन विधायी हस्तक्षेप के कारण उसमें कार्यवाही बंद कर दी गई तमिलनाडु ऋणग्रस्त कृषक (अस्थायी राहत) अध्यादेश, 1975 (1975 का अध्यादेश 1)। धारा 3 के अनुसार किसी ऋण की वसूली के लिए कोई वाद या ऋण की वसूली के लिए किसी मुकदमे में पारित धन के भुगतान की डिक्री के निष्पादन के लिए कोई आवेदन किसी कृषक के विरुद्ध दीवानी या राजस्व न्यायालय में अध्यादेश के प्रभावी होने के वर्ष की दिनांक की समाप्ति से पहले शुरू नहीं किया जा सकता है। अध्यादेश के प्रारंभ होने की तारीख से वर्ष. धारा 4 में धारा में उल्लिखित प्रकृति के मुकदमों या आवेदनों में कार्यवाही पर रोक लगाने का प्रावधान है 3 जिसमें दावा किया गया राहत कृषक के विरुद्ध था, अभिवचनों में संशोधन या परिवर्धन, प्रतिस्थापन, या के लिए कार्यवाही नहीं की जा रही थी पार्टियों को ख़त्म करना, लेकिन अन्यथा अपीलों, पुनरीक्षण याचिकाओं, या आवेदनों में दिए गए आदेशों या डिक्री के परिणामस्वरूप होने वाली समीक्षा कार्यवाहियों को शामिल करना। धारा 5 में प्रावधान है कि किसी ऋण की वसूली के लिए किसी मुकदमे या किसी आवेदन के लिए निर्धारित सीमा की अवधि या समय की सीमा की गणना करते समय ऐसे मुकदमे में पारित डिक्री का निष्पादन, वह समय जिसके दौरान वाद शुरू करना या आवेदन करना धारा 3 द्वारा वर्जित था अध्यादेश के या जिसके दौरान वादी या उसके पूर्ववर्ती-सदस्यतापूर्वक विश्वास करते हुए कि अध्यादेश की धारा 3 ऐसे मुकदमे या ऐसे आवेदन पर लागू होती है, वाद शुरू करने या आवेदन करने से रोका जाएगा, को बाहर रखा जाएगा। प्राप्त डिक्री का निष्पादन पहले ही हो चुका था एक वर्ष की अवधि के लिए निलंबित कर दिया गया।

इसके बाद विधायिका ने तमिलनाडु ऋणग्रस्त कृषक (अस्थायी राहत) अधिनियम, 1975 [1975 का अधिनियम 10] अधिनियमित किया, जिसका उद्देश्य ऋणग्रस्त कृषकों को उनके लेनदारों द्वारा शुरू की गई मुकदमेबाजी में शामिल विकर्षणों और व्यय से बचाने के लिए अस्थायी राहत प्रदान करना था। खाद्य फसलों के उत्पादन का मामला में राज्य को अधिकतम संभावित लाभ हो सकता है। धारा 3, जैसा कि अध्यादेश में है, अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए एक कृषक के खिलाफ एक मुकदमे में पारित धन के भुगतान के लिए डिक्री के निष्पादन के लिए मुकदमे या आवेदन की स्थापना पर रोक लगा दी गई है। . धारा 4 में कार्यवाही पर रोक लगाने का प्रावधान है यदि किसी डिक्री के निष्पादन के लिए मुकदमे या आवेदन पहले ही दायर किए जा चुके हों। दूसरी धारा 5 में परिसीमा की अवधि या निर्धारित समय की सीमा की गणना में समय के अप का प्रावधान है। ऋण की वसूली के लिए वाद या ऐसे मुकदमे में पारित डिक्री के निष्पादन के लिए आवेदन। 1975 के अधिनियम 10 के एक वर्ष की समाप्ति के बाद, विधायिका ने तमिलनाडु ऋणग्रस्त कृषक (अस्थायी राहत) अधिनियम, 1976 अधिनियमित किया [सं. 1976 का 15] 1975 के अधिनियम ।0 के समान उद्देश्य के साथ और मुकदमों की स्थापना और निष्पादन के लिए आवेदनों पर रोक के समान प्रावधानों के साथ, मुकदमों या डिक्री के निष्पादन के लिए आवेदन दाखिल करने के लिए सीमा की अवधि की गणना करते समय कार्यवाही पर रोक और समय का बहिष्कार। इसके बाद, विधायिका ने प्राप्त ऋणों को कम करने के लिए तमिलनाडु ऋण राहत अधिनियम, 1978 (1978 का अधिनियम संख्या 40) अधिनियमित किया।

कृषकों सहित पहले से पारित शासनादेश। निणीर्त ऋणी ने 1978 के अधिनियम 40 के संदर्भ में दिनांक 2.5.1973 की डिक्री को कम करने के लिए एक आवेदन दायर

किया। निष्पादन न्यायालय ने 1978 के अधिनियम 40 के संदर्भ में 18.10.1979 को डिक्री को न्यून कर दिया।

डिक्री धारक ने 1989 की निष्पादन याचिका संख्या 412 दायर की। निणीर्त ऋणी ने आवेदन ई.ए. दायर किया। क्रमांक 399/1991 ई.पी. 1989 की संख्या 412 में कहा गया है कि वर्ष 1989 में डिक्री धारक द्वारा दायर निष्पादन याचिका सीमा की अवधि से परे थी, इसे मूल डिक्री दिनांक 2.5.1973 के पारित होने की तारीख से 12 साल बाद दायर किया गया था। प्रार्थना की गई कि निष्पादन याचिका संख्या 412 सन् 1989 की कार्यवाही समाप्त की जाये। डिक्री धारक का मामला यह था कि निष्पादन याचिका सीमा के भीतर थी क्योंकि इसे भीतर ही दायर किया गया था। मूल डिक्री को छोटा करने और 18.10.1979 को संशोधित डिक्री पारित होने के 12 वर्ष। निष्पादन न्यायालय ने निणीर्त ऋणी की ओर से प्रस्तुत विवाद को स्वीकार नहीं किया और ई.ए. को खारिज कर दिया। उनके द्वारा दाखिल संख्या 399 of 1991. यह माना गया कि परिसीमा अधिनियम, 1963 के अनुच्छेद 136 के तहत निष्पादन याचिका दायर करने की सीमा डिक्री में संशोधन की तारीख से शुरू होगी क्योंकि यह उस तारीख से है जब डिक्री लागू होने योग्य हो गई है।

कार्यकारी अदालत द्वारा पारित आदेश के खिलाफ व्यथित होकर, देनदार ने मद्रास उच्च न्यायालय में 1992 की सीआरपी संख्या 3540 दायर की, जिसे स्वीकार कर लिया गया। उच्च न्यायालय ने माना कि ई.पी. 1989 का क्रमांक 412 सीमा अवधि से परे दायर किया गया था। कि डिक्री के क्रियान्वयन के लिए 12 वर्ष की सीमा दिनांक से चलनी प्रारम्भ हो जायेगी मूल डिक्री अर्थात 2.5.1973 को पारित करना न कि संशोधित डिक्री दिनांक 18.1.0.1979 से। उपरोक्त से व्यथित होकर डिक्री धारक द्वारा विशेष अनुमति याचिका दायर की गई थी जिसमें अवकाश स्वीकृत किया गया है। यहां

यह उल्लेख किया जा सकता है कि डिक्री धारक ने निष्पादन याचिकाएं 62/1980, 12/1981 और 681/1984 दायर कीं। निर्णित ऋणी के विरूद्ध तीन बार गिरफ्तारी वारंट जारी किये गये। एक बार उसे गिरफ्तार कर लिया गया लेकिन वह हिरासत से छूटकर फरार हो गया। डिक्री धारक द्वारा दायर एक आवेदन पर, उसका संपत्ति को नीलामी बिक्री के लिए लाया गया था। निणीर्त ऋणी ने रुपये जमा किये। 50 और रु. डिक्री योग्य राशि के भुगतान के लिए 100 रु. मामला थाडिक्री योग्य राशि का भुगतान करने के लिए निणीर्त ऋणी के अनुरोध पर असंख्य बार स्थगित किया गया, लेकिन गिरफ्तारी और नीलामी के लिए प्रकाशन के बावजूद अपनी संपत्ति की बिक्री पर निणीर्त ऋणी डिक्री राशि जमा करने में विफल रहा।

डिक्री-धारक की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री नेदुमरन ने तर्क दिया है कि परिसीमा अधिनियम, 1963 के अनुच्छेद 136 के प्रयोजन के लिए (इसके बाद इसे "अधिनियम"के रूप में संदर्भित किया गया है) परिसीमा का प्रारंभिक बिंदु डिक्री की तारीख नहीं है, बल्कि वह तारीख है जब डिक्री लागू करने योग्य हो जाती है। डिक्री द्वारा दायर निष्पादन आवेदन संख्या 226/1973 में कार्यवाही।

ऊपर वर्णित अनुच्छेद के अवलोकन से, यह स्पष्ट है कि किसी भी सिविल न्यायालय के डिक्री (अनिवार्य निषेधाज्ञा देने वाले डिक्री के अलावा) या आदेश के निष्पादन के लिए 12 वर्ष की अवधि निर्धारित है। . कॉलम 3 दो भागों में है जो उस समय को दर्शाता है जब से सीमा की अवधि शुरू होती है, अर्थात, सीमा का प्रारंभिक बिंदु; वही हैं (i) जब डिक्री या आदेश लागू करने योग्य हो जाता है और (ii) जहां डिक्री या कोई भी बाद का आदेश पैसे के किसी भी भुगतान या किसी संपत्ति प्रदान को एक निश्चित तिथि पर या आवर्ती अवधि में करने का निर्देश देता है जब डिफ़ॉल्ट होता है, भुगतान या वितरण जिसके संबंध में निष्पादन की मांग की गई है, होता है।

प्रावधान कहता है कि स्थायी निषेधाज्ञा देने वाले डिक्री के प्रवर्तन या निष्पादन के लिए कोई सीमा अवधि नहीं होगी। वर्तमान मामले में, हम उपर्युक्त शुरुआती बिंदुओं में से पहले से संबंधित हैं, अर्थात्, डिक्री या आदेश कब लागू करने योग्य हो जाता है।

परिसीमा अधिनियम, 1963 (1963 का अधिनियम 36) के अधिनियमन से पहले निष्पादन के उद्देश्यों की परिसीमा को धारा के तहत निपटाया गया था सिविल प्रक्रिया संहिता के 48 (संक्षेप में "सीपीसी") और 1908 के सीमा अधिनियम के अनुच्छेद 182 और 183। हम वर्तमान मामले में अनुच्छेद 183 से संबंधित नहीं हैं क्योंकि यह स्थापित न्यायालयों के डिक्री और आदेशों के निष्पादन पर लागू था। रॉयल चार्टर और सुप्रीम कोर्ट द्वारा। सीपीसी की धारा 48 और अनुच्छेद 182 में डिक्री के निष्पादन को शामिल किया गया है। सभी सिविल न्यायालयों के आदेश। धारा 48 में कहा गया है कि "जहां एक डिक्री को निष्पादित करने के लिए एक आवेदन किया गया है जो निषेधाज्ञा देने वाली डिक्री नहीं है, उसी डिक्री के निष्पादन के लिए कोई आदेश उस तारीख से 12 साल की समाप्ति के बाद प्रस्तुत किए गए किसी भी आवेदन पर नहीं किया जाएगा। डिक्री को निष्पादित करने की मांग की गई।"इसलिए धारा 48 में समाप्ति से पहले अधिकतम 12 वर्ष की अवधि प्रदान की गई, जिसके निष्पादन के लिए कोई भी नया आवेदन किया जा सकता था और 12 वर्षों के बाद डिक्री लागू होना बंद हो जाती थी। अनुच्छेद 182 पहले और क्रमिक निष्पादन आवेदनों को नियंत्रित करता है जिन्हें डिक्री-धारक सीपीसी के तहत ऐसी अधिकतम अवधि के भीतर दाखिल कर सकता है। अनुच्छेद 182 में यह भी प्रावधान है कि ऐसे आवेदन अनुच्छेद में निर्दिष्ट समय के विभिन्न बिंदुओं से तीन साल की अवधि के भीतर किए जाने चाहिए। एक सक्षम निष्पादन याचिका को दोनों आवश्यकताओं को पूरा करना होगा।

भारत के विधि आयोग ने अपनी तीसरी रिपोर्ट में महसूस किया कि अनुच्छेद 182 मुकदमेबाजी का एक बहुत ही उपयोगी स्रोत था और हाथों में एक हथियार बन गया था। बेईमान डिक्री-धारक और बेईमान निर्णय-देनदार दोनों का। विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट में अनुसंशा की कि किसी भी सिविल कोर्ट के डिक्री या आदेश के निष्पादन के लिए सीमा की अधिकतम अवधि उस तारीख से 12 वर्ष होनी चाहिए जब डिक्री या आदेश लागू होने योग्य हो (जो आमतौर पर डिक्री की तारीख होती है) या जहां डिक्री या उसके बाद का आदेश पैसे के किसी भी भुगतान या किसी संपत्ति की डिलीवरी को एक निश्चित तारीख या आवर्ती अवधि में करने का निर्देश देता है, ऐसा करने में चूक की तारीख ·भुगतान या वितरण जिसके संबंध में आवेदक डिक्री निष्पादित करना चाहता है। यह अनुशंसा की गई थी कि डिक्री-धारक को डिक्री को जीवित रखने के लिए बाध्य करने वाले प्रावधान की कोई आवश्यकता नहीं थी। हर तीन साल में आवेदन. आम तौर पर, डिक्री धारक को निर्धारित अवधि के भीतर अपनी डिक्री का एहसास करना होता है लेकिन एक अपवाद बनाना आवश्यक था।

इस आशय का कि न्यायालय 12 वर्ष की अवधि की समाप्ति के बाद प्रस्तुत आवेदन पर डिक्री के निष्पादन का आदेश दे सकता है, जहां निर्णय ऋणी ने आवेदन की तारीख से तुरंत 12 वर्षों के भीतर किसी समय धोखाधड़ी या बल द्वारा डिक्री के निष्पादन को रोका था। सीपीसी की धारा 48 को हटाया जा सकता है और इसके प्रावधानों को अधिनियम में शामिल किया जा सकता है। यह अनुसंशा की गई कि अनुच्छेद 183 को हटा दिया जाना चाहिए।

भारत के विधि आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसरण में सीपीसी की धारा 48 को अधिनियम की धारा 28 द्वारा निरस्त कर दिया गया था और अनुच्छेद 182 को वर्तमान अनुच्छेद 136 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। जैसा कि पहले इस निर्णय में

देखा गया था, अधिनियम का अनुच्छेद 136 वैधानिक प्रावधान है, जो डिक्री या आदेश लागू होने पर 12 वर्ष की अवधि निर्धारित करता है।

हमीद जौहरन बनाम अब्दुल सलाम, [2001] 7 एससीसी 573 में इस न्यायालय ने, विभिन्न शब्दकोशों से "प्रवर्तन"शब्द के लिए बताए गए अर्थ का उल्लेख करने के बाद माना कि शब्द "जब डिक्री या आदेश बन जाता है, प्रवर्तनीय"को उनके शाब्दिक अर्थ में पढ़ा जाना चाहिए और विधायिका की मंशा के अनुसार डिक्री बनने की तारीख से 12 वर्ष की अवधि की गणना की जानी चाहिए। यह देखा गया कि अनुच्छेद 136 में विधायिका द्वारा इस्तेमाल की गई भाषा को यदि उचित परिप्रेक्ष्य में पढ़ा जाए तो वह किसी भी बात को स्पष्ट करने के लिए रही होगी। भ्रम जो "डिक्री या आदेश की तारीख"अभिव्यक्ति के उपयोगकर्ता के कारण उत्पन्न हो सकता है जिसका उपयोग पिछले अधिनियम में किया गया था। किसी डिक्री को लागू करने के मामले में परिसीमा अधिनियम की आवश्यकता वह तारीख है जिस दिन डिक्री लागू होने योग्य या लागू होने के योग्य हो जाती है। विधायिका की मंशा स्पष्ट एवं स्पष्ट होने के कारण क़ानून में प्रयुक्त शब्दों के शाब्दिक अर्थ के अलावा कोई अन्य अर्थ उत्पन्न नहीं होता।

सीपीसी की धारा 48, जो डिक्री के निष्पादन के लिए 12 वर्ष की सीमा प्रदान करती है, को अधिनियम के अनुच्छेद 136 द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है। शब्द 'जब डिक्री लागू करने योग्य हो जाती है'जो अनुच्छेद 136 में जगह पाते हैं, सीपीसी की धारा 48 में नहीं थे। विधायिका द्वारा लाए गए परिवर्तन के कारण सीमा का प्रारंभिक बिंदु वह तारीख होगी जिस दिन डिक्री निष्पादन में सक्षम हो जाती है। वर्तमान मामले में डिक्री में किया गया संशोधन पर्याप्त था और सीपीसी की धारा 152 के तहत लिपिकीय या अंकगणितीय गलती के सुधार की तरह महत्वहीन नहीं था। 1978 के अधिनियम 40 के संदर्भ में डिक्री को कम करने के कारण डिक्री की राशि काफी हद

तक कम हो गई थी। फातिमुन्निसा बेगम बनाम मोहम्मद में एक विद्वान एकल न्यायाधीश। ज़ैनुलबुद्दीन साहब, एआईआर (1986) एपी 355, पर भरोसा करते हुए अधिनियम के अनुच्छेद 136 में अभिव्यक्ति "जब डिक्री लागू करने योग्य हो जाती है"जो कि सीपीसी की धारा 48 में नहीं है, ने निष्कर्ष निकाला कि जो डिक्री एक संशोधन के अधीन थी उसे केवल संशोधित के रूप में लागू किया जा सकता है और सीमा की अवधि केवल उसी से शुरू होगी डिक्री के संशोधन की तिथि. विद्वान एकल न्यायाधीश ने इस प्रकार निर्णय दिया:

"अगला निर्णय जिस पर भरोसा किया गया था वह ओसेफ बनाम लोना, एआईआर (1979) केआर 14 था। यह निर्णय निस्संदेह उत्तरदाताओं के मामले का समर्थन करता है। लेकिन मैं सिद्धांत से सहमत होने में असमर्थ हूं इस निर्णय में प्रतिपादित किया गया है। इसमें कोई संदेह नहीं है, धारा 48 का सिद्धांत अब अनुच्छेद 136 में सन्निहित है, जो डिक्री के निष्पादन के लिए 12 साल की सीमा अवधि प्रदान करता है, लेकिन शुरुआती बिंदु अनुच्छेद 136 की व्यक्त भाषा के संदर्भ में निर्धारित किया जाना चाहिए जो कहता है "जब डिक्री लागू करने योग्य हो जाती है"। ये शब्द धारा 48 में नहीं थे। मेरी राय में, उचित व्याख्या यह होगी कि जिस डिक्री को लागू करने की मांग की गई है, उसकी तारीख से अवधि की गणना की जाए, यानी, यदि कोई अपील है, तो यह अपीलीय है। डिक्री और यदि कोई संशोधन होता है तो वह संशोधित डिक्री की तिथि से होता है। जैसा कि मैंने पहले कहा, प्रतिज्ञान के मामले में भी, यदि समय अपीलीय डिक्री की तारीख से चलना शुरू होता है, न कि मूल डिक्री की, तो डिक्री के मामले में तो और भी अधिक। संशोधित किया गया क्योंकि मूल डिक्री अब अपना स्वरूप बरकरार नहीं रखती है। संशोधन सीमा का एक नया प्रारंभिक बिंदु देता है। भले ही अनुच्छेद 136 में 'अपील के मामले में'शब्द शामिल नहीं हैं, न्यायालयों ने माना है कि यह

अपीलीय डिक्री है जो प्रासंगिक है क्योंकि अंततः यह वह डिक्री है जो निष्पादन में सक्षम हो जाती है। संशोधन के मामले में, मूल डिक्री अब अपना स्वरूप बरकरार नहीं रखती है और जिसे निष्पादित करने की मांग की जाती है वह संशोधित डिक्री है। इसलिए, 'प्रवर्तनीय'शब्द का अर्थ उस डिक्री के संदर्भ में किया जाना चाहिए जिसे लागू करने की मांग की गई है। संशोधन की तिथि से गणना करते हुए, दायर निष्पादन याचिका समय के भीतर है।"

हमारी राय में, उपरोक्त मामले में विद्वान एकल न्यायाधीश ने अनुच्छेद 136 के दायरे की सही व्याख्या की है। हम व्यक्त किए गए विचार से सहमत हैं कि संशोधन के मामले में मूल डिक्री अब अपना स्वरूप बरकरार नहीं रखती है और जो निष्पादित करने की मांग की जाती है वह संशोधित डिक्री है . "प्रवर्तनीय"शब्द है उस डिक्री के संदर्भ में समझा जाना चाहिए जिसे लागू करने की मांग की गई है। वर्तमान मामले में, जैसा कि ऊपर कहा गया है, डिक्री-धारक ने वर्ष 1973 में ही निष्पादन के लिए एक आवेदन दायर किया था, लेकिन विधायी हस्तक्षेप के कारण इसकी कार्यवाही बंद कर दी गई और अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई, जो विधायिका द्वारा 1978 के अधिनियम संख्या 40 को लागू करने तक जारी रही। किसानों द्वारा प्राप्त ऋणों को कम करने का प्रावधान किया गया, जिसमें पहले से पारित डिक्री भी शामिल है। इस विधायी अधिनियम के अनुसरण में डिक्री-धारक के पक्ष में पारित डिक्री को काफी हद तक कम कर दिया गया और डिक्री को रद्द कर दिया गया।

1978 के अधिनियम संख्या 40 के दसवें भाग में 18.1 0.1979 को संशोधन किया गया। यह वह डिक्री है जो लागू करने योग्य बन गई। इस तिथि से पहले डिक्री-धारक विधायी हस्तक्षेप के कारण अपने डिक्री को लागू नहीं कर सका। मूल डिक्री लागू नहीं की जा सकी. यह केवल संशोधित डिक्री है जिसे लागू किया जा सकता है। जब

किसी डिक्री के निष्पादन के लिए विधायी रोक थी और बाद में विधायी हस्तक्षेप के कारण डिक्री को छोटा और संशोधित करना पड़ा, फिर डिक्री की प्रवर्तनीयता तब शुरू होगी जब रोक समाप्त हो जाएगी या डिक्री में संशोधन और कटौती की तारीख से शुरू होगी। यदि 12 वर्ष की अवधि को डिक्री के संशोधन की तिथि से गिना जाता है तो डिक्री धारक द्वारा 18.9.1989 को दायर निष्पादन याचिका परिसीमा की अवधि के भीतर है।

इसके अलावा, अभिलेख के सत्यापन पर हमने पाया कि डिक्री-धारक पूरी तरह से सतर्क रहा है और वसूली के लिए अनेक कार्यवाही शुरू की है।

डिक्री योग्य राशि को वर्ष 1973 में दायर पहले निष्पादन आवेदन को विधायी हस्तक्षेप के कारण अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया था। डिक्री में संशोधन के बाद उन्होंने निष्पादन याचिका संख्या 62 वर्ष 1980, 12 वर्ष 1981 और 680 वर्ष 1984 दायर की। निर्णय-ऋणी के खिलाफ तीन बार गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए। एक बार उसे गिरफ्तार कर लिया गया लेकिन वह हिरासत से भाग गया और फरार हो गया. उनकी संपत्ति को बिक्री के लिए रखा गया था। निर्णय-ऋणी ने रुपये जमा किये. 50 और रु. डिक्री योग्य राशि के भुगतान के लिए रु.100। मामला निर्णय-ऋणी के अनुरोध पर कई बार स्थगित किया गया, लेकिन डिक्री को संतुष्ट करने, उसकी गिरफ्तारी और उसकी संपत्ति बेचने के प्रकाशन के लिए दिए गए स्थगन के बावजूद, निर्णय-ऋणी डिक्री राशि जमा करने में विफल रहा था।

ऊपर बताए गए कारणों से, यह अपील खर्चे सहित स्वीकार की जाती है। उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया गया है और निष्पादन न्यायालय के आदेश को पुनः स्थापित कर दिया गया है। निष्पादन न्यायालय अब निष्पादन याचिका पर आगे बढ़ेगा और कानून के अनुसार इसका निस्तारण करेगा। चूंकि डिक्री वर्ष 1973 की है,

इसलिए हम निष्पादन न्यायालय से अनुरोध करेंगे कि निष्पादन याचिका को प्राथमिकता के आधार पर और यदि संभव हो तो इस आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर निस्तारित किया जाए।

कार्यालय को मूल अभिलेख तत्काल निष्पादन न्यायालय को वापस भेजने का निर्देश दिया जाता है।

के.के.टी.

अपील की अनुमति.

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी ललित पुरोहित (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।